

‘इण्डो- यूएस ट्रेड डील पर चार-पांच दिन में दोनों देश संयुक्त बयान देंगे’

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि संयुक्त वक्तव्य के बाद वाइट हाउस के एज़ीक्युटिव आदेश से यूएस टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत रह जाएगा

-डॉ. सतीश मिश्रा-

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 05 फरवरी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है और दोनों देश चार-पांच दिनों में संयुक्त बयान जारी करेंगे। सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा दृथ सोशल पर की गई घोषणा के बाद दिल्ली और वाशिंगटन के बीच समझौते की पहली जानकारी सामने आने लगी है। गोयल ने कहा कि संयुक्त बयान के बाद वाइट हाउस के कार्यकारी आदेश के जरिए अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत तक कम हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने में 30-45 दिन लगेंगे और इसे मार्च में साइन किया जाएगा।

- पीयूष गोयल ने बताया कि औपचारिक एग्रीमेंट होने में 30 से 45 दिन लगेंगे और संभवतया मार्च तक एग्रीमेंट हो जाएगा और इस पर मार्च में वर्चुअली साइन किये जाएंगे।
- ट्रंप ने ट्रेड डील की घोषणा सोमवार रात की थी जिसमें यह भी कहा था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। इसे स्पष्ट करते हुए वाणिज्य विभाग के अफसरों ने बताया कि विमान खरीद के ही ऑर्डर 70-80 अरब डॉलर के होंगे। भारत ईंधन, विमान व चिप्स खरीद पर 300 अरब डॉलर खर्च करेगा।
- वेनेज़ुएला से ईंधन खरीदने के ट्रंप के दावे पर विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, वेनेज़ुएला हमारा पुराना सहयोगी है, हम उससे तेल खरीदते रहे हैं। पर प्रवक्ता ने रुस से तेल खरीद के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा।

उन्होंने बताया कि संयुक्त समझौते पर वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे और संयुक्त बयान के बाद कार्यकारी आदेश के जरिए भारत से आने वाले सामान पर अमेरिकी शुल्क 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा। गोयल ने कहा, “हम चाहते हैं कि समझौता जल्दी हो, क्योंकि इसके बाद हमें और रियायतें मिल सकती हैं।” वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, “मार्च में लीगल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत अमेरिका के सामान पर शुल्क कम करेगा।” ट्रम्प के इस दावे पर भी कुछ स्पष्टता सामने आई कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। व्यापार अधिकारियों ने बताया कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार चुनाव में “कैश ट्रांसफर” के मुद्दे पर आज सुनवाई संभव

चुनाव आचार संहिता के दौरान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दस हजार रु. देने के खिलाफ प्रशांत किशोर ने याचिका दायर की है

- जाल खंबाता -
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 5 फरवरी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जन सुराज पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकार की कल्याण योजना के दुरुपयोग के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वह विधानसभा चुनाव रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। किशोर की पार्टी ने 2025 के चुनावों में 243 विधानसभा सीटों में से 242 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में असफल रही। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का मुख्य मुद्दा बिहार सरकार द्वारा चुनावों से ठीक पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हर परिवार की

- इस योजना के तहत सभी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दस-दस हजार रु. दिए गए थे और वादा किया गया था कि आकलन के बाद काम संतोषप्रद रहा तो 2 लाख रु. और दिए जाएंगे।
- प्रशांत किशोर ने याचिका में आरोप लगाया है कि यह योजना विधानसभा की मंजूरी के बिना मंत्रिमंडलीय फैसले के आधार पर लागू कर दी गई थी और इसके लिए सरकार के आकस्मिक कोष से फंड जुटाया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 267 का उल्लंघन था।
- उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू था तब 1.56 करोड़ महिलाओं के खातों में दस-दस हजार रु. दिए गए थे, यह “भ्रष्ट आचरण” है।

एक महिला को 10,000 रु. सीधे देने का निर्णय लिया था, ताकि वह स्व-रोजगार शुरू कर सके, साथ ही एक और वादा किया गया 2 लाख रु. का, जो

व्यवसाय का आकलन के बाद दिया जाएगा। याचिका के अनुसार, इस योजना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- विवाह पंजीकरण नहीं होने से ईसाई दंपतियों को पासपोर्ट, वीज़ा सहित अन्य सरकारी सेवाओं के लिये कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अधोन नहीं रखा जा सकता। जरिस्टस पीएस भाटी और जरिस्टस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सिरो-मालाबार रोमन कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट ईचार्ज फादर पॉल पी की ओर से दायर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनावों में बढ़ते “रेवड़ी कल्चर” पर सुप्रीम कोर्ट का रुख गंभीर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस विषय पर गंभीर चिंतन की जरूरत है इसलिए इस पर तीन सदस्यीय बैंच विचार करेगी

- जाल खंबाता -
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 5 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनावी घोषणापत्र और चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं के वादे करने का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सार्वजनिक हित से जुड़े गंभीर सवाल उठाता है और इस पर तीन जजों की बैंच को विचार करना चाहिए। यह टिप्पणी उस समय की गई जब भाजपा नेता और वकील याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बैंच के सामने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनावी घोषणापत्र और प्रचार के दौरान मुफ्त योजनाओं की घोषणा पर रोक लगाने की मांग की है। यह संकेत देते हुए कि मामला बड़ी बैंच के सामने रखा जाएगा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण

- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व जरिस्टस जॉयमाल्या बागची की बैंच ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा, यह जनहित का गंभीर मुद्दा है और इसे तीन सदस्यीय बैंच द्वारा सुना जाना चाहिए। इसे मार्च में सुना जाएगा तब तक इंतज़ार कीजिए।
- याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनावों में मुफ्त सामान बांटने के “रेवड़ी कल्चर” पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि 5 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब सिर्फ सूरज, चांद देने का वायदा किया जाना ही बचा है।
- राजनैतिक दलों ने इस याचिका का विरोध किया तथा इसे राजनैतिक रूप से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं व सब्सिडी शासन का अस्म् भाग हैं इसका लक्ष्य कमज़ोर तबकों की मदद करना होता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी सुनवाई के दौरान मुद्दे को जटिल बताया था और अपनी न्यायिक सीमाओं की मजबूरी का उल्लेख किया था।

और सार्वजनिक हित का मामला है... इसे तीन जजों की बैंच को सुनना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस महीने के बाद मामले की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा, “मार्च तक

इंतज़ार करें।” उपाध्याय ने अदालत से मामले की तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि आने वाले महीनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले

हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल वोटरों को प्रभावित करने के लिए लगातार वादे कर रहे हैं, जो उनके अनुसार भ्रष्ट आचरण है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुरुवार को ठप्प रही लोकसभा

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। लोकसभा में गुरुवार को भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

तीन बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे शुरू होते ही विपक्षी सदस्य फिर से नारेबाजी करने

- लोकसभाध्यक्ष ने दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित करते हुए कहा सदस्य पोस्टर लेकर आएं तो सदन नहीं चलेगा।

लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के बीच कहा कि बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल कुछ सदस्यों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया और ऐसे दृश्यों का सुजन किया, वह लोकसभा के शुरुआत से लेकर आज तक आज तक कभी नहीं हुआ। संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का परिणामपत्र स्थान हमारे संविधान में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

को अपने कट्टर दुश्मन, खासकर यूरोप और यूरोपीय संघ के सामने पीछे छूटना पसंद नहीं आया। ट्रम्प को खोई हुई जमीन को वापस पाने की तत्काल ज़रूरत महसूस हुई और वे मौके की तलाश में थे। उन्होंने वाशिंगटन से ट्रेड डील की एकतरफा घोषणा कर दी, जिससे भारतीय पक्ष हैरान रह गया। घोषित व्यापार समझौता भारत के लिए इतना आकर्षक बताया गया कि उसे केवल घोषणा कहकर टुकराना मुश्किल था। हालांकि भारत ने यह नहीं कहा कि कोई पक्का व्यापार समझौता हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिंहाचार के तौर पर राष्ट्रपति की घोषणा का स्वागत किया। इस तरह अब केवल अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के बड़े

- हालांकि, ट्रेड डील को लेकर अभी सिर्फ कयास ही लग रहे हैं लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अमेरिका की दबाव डालने की रणनीति भारत पर कारगर नहीं हुई और यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील से तो अमेरिका की हताशा और बढ़ गई।
- यही वजह रही कि कभी भारत को “डैड इकॉनमी” बताने वाले ट्रंप ने खुद ही ट्रेड डील स्वीकृत करने की घोषणा कर दी क्योंकि ट्रंप समझ गए कि भारत का विशाल बाजार उनके हाथ से निकल रहा है।
- घोषणा अमेरिका की तरफ से हुई और डील भी बेहद आकर्षक थी, ऐसे में भारत के इन्कार करने का सवाल नहीं था।
- पर अब देखना यह है कि वास्तव में यह डील क्या रूप लेती है और भारत को कितना लाभ देगी।

विचार बिन्दु

बच्चों को पालना, उन्हें अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना भी सेवाकार्य है, क्योंकि यह उनका जीवन सुखी बनाता है। –स्वामी रामसुखदास

लोकलुभावन नहीं 2047 के भारत की इबारत है नया बजट

संभवतः यह पहला अवसर होगा जब केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते समय चुनावों में राजनीतिक लाभ हानि पर विचार किये बिना समग्र विकास और दीर्घकालीन आर्थिक सुधार को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। कुछ माहों में ही पं. बंगाल, तमिलनाडू, केरल, असम और पुडुचेरी के चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएगी। अब तक होता यह आया है कि बजट में चुनाव वाले राज्यों के नागरिकों को लुभाने के लिए खास घोषणाएं होती हैं। पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजनीतिक लाभ हानि के स्थान पर समग्र सुधारों और सरकार के मिशन 2047 को केन्द्र में रखकर 2027-28 का बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां बजट पेश किया है। खासबात यह कि 2019 से 2026 तक लगातार नवां बजट पेश करने तक वित्त मंत्री सीतारमण भिन्न भिन्न प्रदेशों की हथकरघा साड़ियों में नजर आई है। इस बार तमिलनाडू की बैंगनी कांजीवरम सिल्क साड़ी में नवां बजट पेश किया।

इस साल का बजट इसलिए भी मायने रखता है कि दुनिया के देशों के हालात और वैश्विक परिस्थितियां दिन प्रतिदिन विपरीत होती जा रही हैं। बजट के दिन जहां शेयर बाजार धराशाही हो गया वहीं दूसरे दिन ही अमेरिका द्वारा टैरिफ दर कम करने के साथ ही शेयर बाजार ने उंची उड़ान भर डाली। पर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की आर्थिक विकास की गति बनाए रखना किसी गंभीर चुनौती से कम नहीं है। विपरीत हालातों में भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हमारी है। दुनिया के देश जहां आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था ने उंचाई प्राप्त की है। अमेरिका में ट्रंप 2 के बाद से दुनिया के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं पर जिस रणनीति से भारत ने अमेरिका को इन्फोर की नीति पर चलते हुए चुनौती दी इसी का परिणाम है कि ट्रंप को टेरिफ दरें घटानी पड़ी है। हालांकि ट्रंप के मिजाज को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब बह पलटी मार जाए।

केन्द्रीय बजट की इसलिए सराहना की जानी चाहिए कि वैश्विक हालातों को देखते हुए दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, देश में ढांचगत विकास और युवाओं, महिलाओं, किसानों सभी को साधने का जो समग्र प्रयास हुआ है उससे निश्चित रूप से आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी। विश्लेषक इसे समग्र सुधारों के साथ विकास का संकल्प बता रहे हैं तो कोई इस बजट को भारत की

कहने को लाख आलोचनाएं की जा सकती हैं पर वैश्विक हालातों को देखते हुए जिस तरह का भविष्योन्मुखी ठोस आधारभूत विकास का बजट होने से इससे दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोकलुभावन ही नहीं आमजन दीर्घकालीन आर्थिक विकास के बजट का आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। अब बजटीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का भी समयबद्ध रोडमैप बन जाए तो निश्चित रूप से इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

युद्ध में बदल जाएं कहा नहीं जा सकता है और पाकिस्तान कब अपनी उद्दंडता दिखा दे कुछ कहा नहीं जा सकता, चीन के इरादे हमेशा संदिग्ध रहे हैं ऐसे में रक्षा क्षेत्र में बजटीय प्रावधान बढ़ाना और सैन्य क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना समय की मांग है। इसी तरह से डिजिटल युग में दुनिया के देशों से दो कदम आगे बढ़ना समय की मांग है। एआई के युग को देखते हुए एआई को रोजगार का माध्यम बनाना, कौशल विकास, तकनीक से शिक्षा को जोड़ने, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, यहां तक कि गाइड्स तैयार करने से लेकर चुनावों और रोजगार से जुड़े सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के प्रावधान किये गये हैं। खेती-किसानी को प्रोत्साहित करने के साथ ही जल के महत्व को समझा गया है। अमृत सरोवर से जल संग्रहण से लेकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बेहतर लोजिस्टिक प्रमुख आवश्यकता है। रक्षा के बाद सबसे अधिक प्रावधान बेहतर कनेक्टिविटी को दिया गया है। बेहतर आवागमन से विकास को गति मिलती है तो योजनाबद्ध शहरी विकास पर जोर दिया गया है। यदि सार रूप में कहा जाए तो यह बजट आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने का रोडमैप कहा जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र को गति, आधारभूत संरचना विकास, कौशल विवकास, एमएसएमई को प्रोत्साहन, उर्जा विकास व सहज उपलब्धता, इकोसिस्टम बनाए रखते हुए समग्र विकास पर जोर रहा है। हालांकि नौकरी पेशा लोग आयकर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने से निराश हुए हैं तो शेयर मार्केट में सर्ट्-टबाजी को निरुत्साहित करने से निराशा हुई और इसका तत्काल असर शेयर बाजार पर देखा गया। कहने को लाख आलोचनाएं की जा सकती है पर वैश्विक हालातों को देखते हुए जिस तरह का भविष्योन्मुखी ठोस आधारभूत विकास का बजट होने से इससे दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोकलुभावन ही नहीं आमजन दीर्घकालीन आर्थिक विकास के बजट का आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। अब बजटीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का भी समयबद्ध रोडमैप बन जाए तो निश्चित रूप से इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल

शुक्रवार 6 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, हस्त नक्षत्र रात्रि 12:2 तक, धृति योग रात्रि 11:37 तक, कौलव करण दिन 12:51 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

गृहस्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज कुमार योग सूर्योदय से रात्रि 12:24 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:36 तक, लाभ-अमृत 8:36 से 11:19 तक, शुभ 12:41 से 2:03 तक, चर 4:46 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 6:08



मेघ

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होंगे। अस्त-व्यस्त दिवचार्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



तुला

व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में पेशानी हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।



वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वृश्चिक

आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।



मिथुन

घर-परिवार में सुख-शान्ति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।



धनु

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कर्क

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रो/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।



मकर

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।



कुंभ

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।



कन्या

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।



मीन

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

ट्रंप डील और मोदी नेतृत्व

राजस्थान के उद्योग के लिए नए अवसरों का द्वार



अशोक परनामी

भारत और अमेरिका के बीच लंबे इंतजार के बाद संपन्न हुई नई ट्रेड डील ने न केवल दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई दी है, बल्कि राजस्थान जैसे निर्यात-आधारित राज्यों के लिए यह समझौता उम्मीदों का नया क्षितिज खोलता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ की घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय ऐसे समय आया है, जब वैश्विक बाजार में अस्थिरता और संरक्षणवाद

की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इस प्रष्ठभूमि में यह समझौता भारत की बढ़ती वैश्विक साख और प्रभावी आर्थिक कूटनीति का प्रमाण माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक समझौते के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार के रूप में स्थापित किया है। 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों को अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता दिलाने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। अमेरिका जैसे प्रभावशाली देश द्वारा टैरिफ में इतनी बड़ी कटौती इस बात का संकेत है कि भारत अब शर्तें तय करने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस डील को 'गेम चेंजर' करार देना भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है कि केंद्र के मजबूत नेतृत्व का सीधा लाभ राज्यों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले छह वर्षों में

ऊर्जा मिली है। अमेरिका जैसे बड़े खरीदार पर काफी हद तक निर्भर स्टोन इंडस्ट्री टैरिफ बढ़ने से सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। 70 प्रतिशत से अधिक इकाइयों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा। अब टैरिफ कटौती के बाद अमेरिकी खरीदारों की सक्रियता बढ़ने से उत्पादन और रोजगार दोनों में सुधार की उम्मीद है। इसी तरह तीन लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला जयपुर का गारमेट उद्योग एक बार फिर रफ्तार पकड़ने को तैयार है। निर्यात में गिरावट से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से राहतभरा साबित हो रहा है। राजस्थान का हस्तशिल्प, ब्लू पॉटरी, लकड़ी का काम, संगमरमर की नक्काशी और हाथ से बने वस्त्र अमेरिकी बाजार में लोकप्रिय रहे हैं। टैरिफ घटने से जयपुर और जोधपुर के कारीगरों को बेहतर दाम और स्थिर बाजार मिलने की संभावना है। यह न केवल आर्थिक लाभ देगा, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी

सहायक होगा। निर्यात में वृद्धि का असर केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। परिवहन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, बैंकिंग और बीमा जैसे सहायक क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ेंगी। यह 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' राजस्थान की अर्थव्यवस्था को व्यापक गति देगा और नए रोजगार सृजित करेगा। भारत-अमेरिका ट्रेड डील और टैरिफ में ऐतिहासिक कटौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टि और प्रभावी आर्थिक कूटनीति का परिणाम है। राजस्थान के लिए यह समझौता केवल व्यापारिक राहत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ वैश्विक बाजार में आगे बढ़ने का अवसर है। यदि राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ उद्योग जगत इस अवसर का सही उपयोग करता है, तो राजस्थान आने वाले वर्षों में निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है और यही इस डील की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

–अशोक परनामी,
पूर्व विधायक एवं
पूर्व मेयर जयपुर।

तारबंदी से सुरक्षा, बीमा से संबल : किसानों को करोड़ों रुपये का अनुदान मिला

विकसित भारत 2047 के सपने के केंद्र में अन्नदाता : सरकारी सहायता और योजनाओं ने खोले रास्ते, किसान ने दुनिया देखी



अमृता कटारा

भारतीय कृषि को अक्सर परंपरा के फ्रेम में बाँधकर देखा गया है-हल, बैल, मानसून और अनिश्चितता। लेकिन आज खेतों की ज़मीन के नीचे सिर्फ बीज नहीं, बदलाव भी दबाहुआ है। यह बदलाव न तो अचानक है और न ही पूरी तरह दृश्यमान होता है। यह धीरे-धीरे किसान की सोच, नीति और खेती में बदलाव की कोशिश कर रही है। एक ओर रक्षा बजट की कोशिश कर रही है। जिस तरह के तनाव के हालात बने हुए हैं और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के हालात रहे, उधर रुस यूक्रेन युद्ध थमने का ही नाम नहीं ले रहा है, ईरान अमेरिका के हालात कब

युद्ध में बदल जाएं कहा नहीं जा सकता है और पाकिस्तान कब अपनी उद्दंडता दिखा दे कुछ कहा नहीं जा सकता, चीन के इरादे हमेशा संदिग्ध रहे हैं ऐसे में रक्षा क्षेत्र में बजटीय प्रावधान बढ़ाना और सैन्य क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना समय की मांग है। इसी तरह से डिजिटल युग में दुनिया के देशों से दो कदम आगे बढ़ना समय की मांग है। एआई के युग को देखते हुए एआई को रोजगार का माध्यम बनाना, कौशल विकास, तकनीक से शिक्षा को जोड़ने, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, यहां तक कि गाइड्स तैयार करने से लेकर चुनावों और रोजगार से जुड़े सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के प्रावधान किये गये हैं। खेती-किसानी को प्रोत्साहित करने के साथ ही जल के महत्व को समझा गया है। अमृत सरोवर से जल संग्रहण से लेकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बेहतर लोजिस्टिक प्रमुख आवश्यकता है। रक्षा के बाद सबसे अधिक प्रावधान बेहतर कनेक्टिविटी को दिया गया है। बेहतर आवागमन से विकास को गति मिलती है तो योजनाबद्ध शहरी विकास पर जोर दिया गया है। यदि सार रूप में कहा जाए तो यह बजट आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने का रोडमैप कहा जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र को गति, आधारभूत संरचना विकास, कौशल विवकास, एमएसएमई को प्रोत्साहन, उर्जा विकास व सहज उपलब्धता, इकोसिस्टम बनाए रखते हुए समग्र विकास पर जोर रहा है। हालांकि नौकरी पेशा लोग आयकर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने से निराश हुए हैं तो शेयर मार्केट में सर्ट्-टबाजी को निरुत्साहित करने से निराशा हुई और इसका तत्काल असर शेयर बाजार पर देखा गया। कहने को लाख आलोचनाएं की जा सकती है पर वैश्विक हालातों को देखते हुए जिस तरह का भविष्योन्मुखी ठोस आधारभूत विकास का बजट होने से इससे दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोकलुभावन ही नहीं आमजन दीर्घकालीन आर्थिक विकास के बजट का आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। अब बजटीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का भी समयबद्ध रोडमैप बन जाए तो निश्चित रूप से इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि की नीति के केंद्र में रखा है। किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, पीएम-कुसुम, अटल भू-जल योजना, किसान डिजिटल आईडी, तारबंदी और जैविक खेती जैसी योजनाएँ यह संकेत देती हैं कि सरकार ने खेती को अल्पकालिक राहत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक योजना मानती है। राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 59 हजार 039 सोलर पंपसेटों की स्थापना कर 900 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया जाना यह बताता है कि सिंचाई और नवीनीकरण ऊर्जा के सवाल को स्थायी समाधान की ओर ले जाया जा रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 6,450 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का वितरण यह दर्शाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय किसान को आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है। खेतों में जोखिम कम हुए बिना नवाचार संभव नहीं होता। नीति का असर तब स्पष्ट दिखता है जब वह ज़मीन पर उतरती है।

राजस्थान में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर इस मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। योजनाओं की जानकारी, आवेदन की प्रक्रिया और समस्याओं का समाधान-सब कुछ एक ही मंच पर उपलब्ध होने से किसानों और प्रशासन के बीच की दूरी कम हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि जागरूकता केवल सूचना से नहीं, संवादसे आती है और यही इन शिविरों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रतापगढ़ जैसे जनजाति क्षेत्रों में यह बदलाव विशेष महत्व रखता है, जहाँ खेती लंबे समय तक केवल जीवन निर्वहण तक सीमित रही। छोटी ज़ोतों और सीमित संसाधनों के बीच प्रतापगढ़ के जवाहरनगर के बाबूलाल मीणा द्वारा सरकार की सहायता से वर्मी कम्पोस्ट यूनित की स्थापना यह बताती है कि जैविक खेती अब प्रयोग नहीं रही। कम लागत, बेहतर मूल्य और अतिरिक्त आय-ये



परिणाम बताते हैं कि सही मार्गदर्शन मिलने पर किसान टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ सकता है।

इसी जिले से किसान शंभूलाल पाटीदार का डेनमार्क एक्सपोजर विजिट पर जाना यह संकेत देता है कि कृषि प्रशिक्षण अब केवल तकनीक सिखाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोच का दायरा भी बढ़ा रहा है। जब किसान दुनिया को देखने लगता है, तो अपनी ज़मीन को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। तारबंदी योजना ने भी खेती को स्थिरता दी है एवं किसानों के हितों की रक्षा की है। जवाहरनगर की दुग्रां बाई मीणा और पिल्लू गाँव के पंकज कुमार मीना जैसे किसानों की कहानियाँ यह बताती हैं कि फसल सुरक्षा केवल नुकसान नहीं रोकती बल्कि कृषि को अधिक सुरक्षित बनाती है।

राज्य में लगभग 34,395 किलोमीटर तारबंदी कर 377.66 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना इस बात का संकेत है कि खेती को जोखिम से मुक्त करने की दिशा में ठोस प्रयास हुए हैं। इसके साथ ही 35,368 फार्म पॉन्ड के निर्माण पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जल संरक्षण को खेती की बुनियाद बनाने की मंशा को दर्शाता है। इन सभी अनुभवों और आँकड़ों को साथ रखकर देखा जाए तो स्पष्ट होता

है कि प्रदेश के अन्नदाताओं का भविष्य जनहितैषी कार्यों की निरंतरता, ज़मीनी क्रियान्वयन और किसान की भागीदारी से आकार ले रहा है। खेत आज भी परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन अब उनके साथ सुरक्षा, ज्ञान और उम्मीद भी खड़ी है-और शायद यही बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कृषि को नवाचार, सुरक्षा और सम्मान से जोड़ने की दिशा में जो व्यापक विजन सामने रखा, उसे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ज़मीन पर आकार मिलता दिख रहा है। सोलर पंप से लेकर फसल बीमा, तारबंदी से लेकर जल संरक्षण तक-ये प्रयास यह संकेत देते हैं कि किसान को अब केवल उत्पादन की इकाई नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सहभागी माना जा रहा है। जनजाति क्षेत्रों से सामने आई बदलाव की यह कहानियाँ यह भरोसा जगाती हैं कि जब नीति में निरंतरता हो और क्रियान्वयन में संवेदनशीलता, तो खेती केवल अतीत की विरासत नहीं रहती, वह भविष्य की बुनियाद बन जाती है।

शंभू लाल पाटीदार: वैश्विक अनुभव और सरकारी योजनाओं से बदली खेत की तस्वीर। प्रतापगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान शंभू लाल पाटीदार ने पारंपरिक

खेती को आधुनिक और लाभकारी कृषि में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती को नई दिशा दी। सरकारी सहयोग से वे पॉलीहाउस में लाल और हरी शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अधिक उत्पादन के साथ बेहतर बाजार मूल्य भी मिल रहा है। उनकी यह सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही तरीके से लागू की गई सरकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ टिकाऊ और नवाचारी कृषि को भी बढ़ावा देती हैं।

हाल ही में शंभू लाल पाटीदार को एक सरकारी कार्यक्रम के तहत डेनमार्क जाने का अवसर मिला, जहाँ उन्होंने उन्नत जैविक खेती की तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने इस अनुभव को अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि वहां उन्होंने उत्पादन बढ़ाने और खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के कई महत्वपूर्ण गुर सीखे। सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल किसानों को वैश्विक ज्ञान, नई दक्षताएं और नवाचार करने का आत्मविश्वास प्रदान करती हैं।

–अमृता कटारा,
एपीआरओ, डीआईपीआर

बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम शुरु

अजमेर, (निर्स)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के सफल, निष्पक्ष एवं सुचारु आयोजन को लेकर गुरुवार को कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। इस अवसर पर बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने विधि-विधान के साथ मां सरस्वती की पूजा-अर्चना कर कंट्रोल

बोर्ड का शुभारंभ किया। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि कंट्रोल रूम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना तथा परीक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। कंट्रोल रूम

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिकारियों परीक्षा के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की परीक्षा, अव्यवस्था या आपात स्थिति की जानकारी सीधे कंट्रोल बोर्ड को दे सकेंगे। प्राप्त सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बोर्ड प्रशासन का मानना है कि कंट्रोल बोर्ड की सक्रिय

अधीक्षक एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षा के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की परीक्षा, अव्यवस्था या आपात स्थिति की जानकारी सीधे कंट्रोल बोर्ड को दे सकेंगे। प्राप्त सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बोर्ड प्रशासन का मानना है कि कंट्रोल बोर्ड की सक्रिय



पंडित अनिल शर्मा

गृहस्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज कुमार योग सूर्योदय से रात्रि 12:24 तक है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:36 तक, लाभ-अमृत 8:36 से 11:19 तक, शुभ 12:41 से 2:03 तक, चर 4:46 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 6:08

‘राजस्थान में खेजड़ी काटने पर रोक नहीं लगेगी, तब तक अनशन जारी रहेगा’

अनशनकारियों ने पूरे राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने की मांग की

बीकानेर, (निर्स)। यहा ‘खेजड़ी बचाओ’ आंदोलन दो फरवरी से चल रहा है। अनशन पर बैठे कई लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। बीकानेर में चल रहे ‘खेजड़ी बचाओ’ आंदोलन के चौथे दिन मंत्री केके विश्नोई ने अनशन पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया तो वहीं सिर्फ जोधपुर और बीकानेर संभाग में खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने का ऑर्डर सुनते ही लोग भड़क गए। कुछ देर बाद लोग फिर अनशन पर बैठ गए और कहा कि जब तक पूरे राजस्थान में खेजड़ी काटने पर रोक नहीं लगेगी तब तक अनशन जारी रहेगा।

आंदोलन की अगुवाई कर रहे परसराम विश्नोई ने बताया कि अनशन खत्म नहीं हुआ है। सतों का कहना था कि भत्ता की भावना थी कि पूरे राजस्थान में रोक लगनी चाहिए। जो ऑर्डर आया वो अधूरा ही था। उन्होंने बताया कि आमरण अनशन चल रहा है। इससे पहले कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता मंत्री केके विश्नोई और राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जयवंत विश्नोई गुस्वार सुबह करीब 11 बजे अनशन स्थल (विश्नोई धर्मशाला) पर पहुंचे। मंच पर संबोधन के दौरान मंत्री के हाथ से माइक ले लिया। मंत्री केके विश्नोई ने कहा कि

■ ‘खेजड़ी बचाओ’ आंदोलन के चौथे दिन मंत्री केके विश्नोई ने अनशन पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वा दिया था

■ वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग में खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने का ऑर्डर सुनते ही लोग भड़के

■ अनशनकारियों का कहना है कि जब तक पूरे राजस्थान में खेजड़ी काटने पर रोक नहीं लगेगी तब तक अनशन जारी रहेगा

आप अनशन तोड़ दीजिए, हम लिखकर दे देंगे। मंच पर मौजूद सतों ने बिना लिखित आश्वासन के अनशन से उठने से इनकार कर दिया। जब केके विश्नोई मंच पर अपनी बात रख रहे थे, तभी संत सरजूदास बीच में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इधर-उधर की बात न करें। सीधा बताएं लिखित में देंगे या नहीं। यदि लिखित में नहीं देंगे तो हम अनशन पर बैठे हैं। केके विश्नोई ने कहा कि सरकार लिखित में देने को तैयार है। आप अनशन तोड़ दीजिए। फलोदी विधायक पन्ब्याम विश्नोई ने अनशन तोड़ने की अपील की। इस दौरान उनका विरोध शुरू हो गया। आंदोलनकारियों ने हंगामा करते हुए कहा कि आश्वासन लिखित में

दिया जाए। इस पर पन्ब्याराम विश्नोई ने कहा कि यदि किसी की जान को नुकसान हुआ, तो आपका, हमारा और सभी का मुंह खराब होगा। इस बयान से लोग और भड़क गए। वे नाराज हो गए और पन्ब्याराम को बैठ जाने के लिए कह दिया। वहीं बुधवार देर रात चार अनशनकारियों को अस्थायी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गुस्वार दोपहर में पर्यावरण जीव रक्षा समिति के अध्यक्ष मुखराम धरणीया की हालत बिगड़ गई। उन्हें पीबीएम हॉस्पिटल पर फरक दिया जाएगा।

बीकानेर में आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए भाजपा उपाध्यक्ष बिहारीलाल बिश्नोई ने कहा कि विपक्षी पार्टी यह भ्रंति फैला रही है कि भाजपा सरकार ने सजा समाप्त कर दी है। हकीकत यह है कि भाजपा सरकार ने केवल गड़रियों (भेड़-बकरी चराने वाले) को जेल जाने से बचाया है। पहले खेजड़ी काटने पर कोई सजा थी

ही नहीं, तो उसे खत्म कैसे किया जा सकता है। जोधपुर की रहने वाली एडवोकेट शारदा विश्नोई ने कहा कि मां अमृता देवी ने खेजड़ी के लिए बलिदान दिया था। हम यहां कोई ढोंग करने नहीं आए हैं। जैसे हम घर पर रहते हैं, वैसे ही पूरे परिधान और आभूषण पहनकर यहां आए हैं। मांगों को लिए सरकार लिखित में देगी तो ही अनशन समाप्त होगा। उन्होंने गुप्त वार्ता करने से इनकार कर दिया। बीकानेर के विश्नोई धर्मशाला में चल रहे अनशन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। राजस्थान समेत हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश से पर्यावरण प्रेमी खेजड़ी बचाने के समर्थन में पहुंचे हैं।

सीएमएचओ मुखराज साध ने बताया कि बिश्नोई धर्मशाला में बने अस्थायी हॉस्पिटल में 18 अनशनकारी भर्ती हैं। पीबीएम हॉस्पिटल में 4 अनशनकारी भर्ती किए गए थे, जिनमें से दो को छुट्टी दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम तक कोई घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल दिनभर बीकानेर आए मंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

राजस्थान सरकार के राजकीय / अर्द्धशासकीय / स्वायत्तशासी निकायों में सक्षम श्रेणी में निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत संवेदकों से समग्र शिक्षा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2024–25, 2025–26, DAJGUA 2024-25, DAJGUA 2025-26, STARS PROJECT 2023-24 राज्य मं 2024–25, 2025–26 एवं नाबाई आर.आई.डी.एफ. XXIX, इत्यादि योजनान्तर्गत स्वीकृत 26 राजकीय विद्यालय / केजीबीबी / हॉस्टल के निर्माण कार्यों हेतु राशि रु. 7328.75 लाख (प्रति कार्य की राशि रुपये 220.59 लाख से 413.73 लाख के मध्य) बाबत कार्यवाह ई-टेंडरिंग के माध्यम से ई-निविदाएं 05/02/2026 प्रातः 10.00 बजे से 24/02/2026 को सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा से सम्बन्धित समस्त विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://rajsmsa.nic.in>, <http://sppp.rajjasthan.gov.in> एवं <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

निविदा से सम्बन्धित प्रक्रिया जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय सम्बन्धित जिला के स्तर से की जायेगी।

UBN No. : RSE2526WSOB06651

राज्य परिवेक्षण निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अनुसूच, स्कूल शिक्षा

रज.सहाय/ली/25/19225

आवारा श्वान ने बालक पर हमला किया

कोटा, (निर्स)। आवारा कुत्तों ने एक तीन वर्षीय मासूम बालक पर हमला कर बच्चे को दो तीन जगह काट लिया। घटना विज्ञान नगर इलाके के सेक्टर एक की है, घटना उस समय हुई जब बालक अपने

दाद के साथ घूम रहा था। देवेन्द्र गंगवाल अपने 3 वर्षीय पेटे विश्रत जैन को इलाके में स्थित मुकेश पार्क में घुमाने गए थे और वापस लौटते समय गली में 3-4 आवारा कुत्ते बालक पर झपट पड़े।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER P.H.E.D CITY DIV. IV (NORTH) JAIPUR
Email: eenorth4.jai.phed@rajasthan.gov.in, Telephone No-0141-2988545
No.: E.E./CD4(N)/2025-26/

Notice Inviting Bid
Bids for work of Improvement of Existing Water Supply System of Ram Nagar Zone, Jhotwara through Ram Nagar OHSR under the Jurisdiction of City Division-IV (North), Vidhyadhar Nagar, Jaipur NIT No 50/2025-26 is invited from interested bidders up to 06:00 PM 05.02.2026. Other particulars of the bid may be visited on the www.sppp.rajjasthan.gov.in and www.eproc.rajjasthan.gov.in of the state website.
UBN Code: PHE 2526WSOB11846

Executive Engineer, PHED City Div.IV (North) Vidhyadhar Nagar Jaipur
DIPRC/1897/2026

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER P.H.E.D CITY DIV. IV (NORTH) JAIPUR
Email: eebadi.dho.phed@rajasthan.gov.in, ee_phedbari@yahoo.com

NOTICE INVITING BID No. 44/2025-26
Online bids for NIT No. 44/2024-25 works costing 60.00 Lacs is invited on behalf of The Governor of Rajasthan from eligible enlisted in appropriate class contractors of PHED, Rajasthan and meeting eligibility criteria. Details of Bid notification and pre-qualification criteria can be seen on web site <http://sppp.raj.nic.in> and <https://eproc.rajjasthan.gov.in>. Bids are to be submitted online in electronic format on web site <https://eproc.rajjasthan.gov.in> from 28.01.2026 to 06.02.2026 at 06:00 PM and bids are to be opened at 03:00 PM on 07.02.2026 in presence of willing bidders/there authorize representative.
NIB: PHE2526A5664
UBN: PHE2526WSOB11831
DIPRC/1828/2026

Executive Engineer, PHED Division Barl

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PHED DHOLPUR
Email : eebadi.dho.phed@rajasthan.gov.in, ee_phedbari@yahoo.com

NOTICE INVITING BID No. 44/2025-26
Online bids for NIT No. 44/2024-25 works costing 60.00 Lacs is invited on behalf of The Governor of Rajasthan from eligible enlisted in appropriate class contractors of PHED, Rajasthan and meeting eligibility criteria. Details of Bid notification and pre-qualification criteria can be seen on web site <http://sppp.raj.nic.in> and <https://eproc.rajjasthan.gov.in>. Bids are to be submitted online in electronic format on web site <https://eproc.rajjasthan.gov.in> from 28.01.2026 to 06.02.2026 at 06:00 PM and bids are to be opened at 03:00 PM on 07.02.2026 in presence of willing bidders/there authorize representative.
NIB: PHE2526A5664
UBN: PHE2526WSOB11831
DIPRC/1828/2026

Executive Engineer, PHED Division Barl

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वा अभि विभाग, खण्ड कोलायत
क्रमांक:- 3210-23

Notice Inviting Bid: 79/2025-26
Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 10.02.2026 at 14.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.rajjasthan.nic.in & "http://eproc.rajjasthan.gov.in" of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 102.76 lacs.

NIT No.	80
UBN No.	PHE2526WSOB12438

अधिशाषी अभियंता

DIPRC/2173/2026

जल सीमित है, इसकी बचत करें।

जन स्वा अभि विभाग, खण्ड कोलायत

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वा अभि विभाग, खण्ड कोलायत
क्रमांक:- 3210-23

Notice Inviting Bid: 79/2025-26
Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 10.02.2026 at 14.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.rajjasthan.nic.in & "http://eproc.rajjasthan.gov.in" of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 102.76 lacs.

NIT No.	80
UBN No.	PHE2526WSOB12438

अधिशाषी अभियंता

DIPRC/2173/2026

जल सीमित है, इसकी बचत करें।

जन स्वा अभि विभाग, खण्ड कोलायत

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER, W.R. PROJECT CIRCLE JHALAWAR
क्रमांक: F- SEWR/Circle/NIT-1/2025-26/8048 दि - 23/01/2026

E-NIT No.- 05/2025-26
Bids for works 1- Construction of Primary School with Interlocking front road at R&R colony Chhatrapur under Parwan Major Multipurpose Irrigation Project Tehsil Atru Dist. Baran. " (Rs. 138.47 Lac) and 2- Construction of Temple, Tree platform, Entrance Gate and Indication Arrow at R&R colony Chhatrapur under Parwan Major Irrigation Project, tehsil-Atru, Distt. Baran. (Rs. 30.22 Lac) are invited from interested bidders (registered in appropriate class) from 28.01.2026 (9:30 AM) to 12.02.2026 till 18:00 Hrs. other particulars, terms & conditions may be seen on the procurement portal eproc.rajjasthan.gov.in, sppp.rajjasthan.nic.in, dipronline.rajjasthan.gov.in and www.water.rajjasthan.gov.in.
NIB No.: WRD2526A0673
UBN No. Item No.-01: WRD2526WSOB02370
UBN No. Item No.-02: WRD2526WSOB02371
DIPRC/1858/2026

(Ajeet Kumar Jain) Superintending Engineer, W. R. Project Circle Jhalawar

MBM UNIVERSITY, JODHPUR (Central Store)
No.: MBMU/OIC/2025-26/1418 Date :- 02/02/2026

NOTICE INVITING BID
Bids are invited from interested eligible and experienced vendors/suppliers for the supply/provision of the following items/services at MBM University, Jodhpur. All other particulars of the bid may be visited on the portal sppp.rajjasthan.gov.in, eproc.rajjasthan.gov.in and www.mbm.ac.in.
1. Bids vide UBN No: MBM2526WSOB00095 Tender No.69/2025-26 for "Tender for Turnkey Execution of CCTV Cameras, facility in classrooms, laboratory rooms and campus Works for University Campus" in MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹220.00Lakh. rupees and last date of bid submission 21.02.2026, 12:00 Noon.
2. Bids vide UBN No: MBM2526WSOB00094 Tender No.68/2025-26 for "E-Tender for Furniture works of Auditorium and other" in MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹106.00 Lakhs and last date of bid submission 21.02.2026 12:00 Noon.
Raj.Samwad/C/25/19220

OIC-Central Store

OFFICE OF THE DIRECTOR RAJASTHAN STATE ARCHIVES, BIKANER
S.No.: bika/dir/arch/Store/E-NIB-02/2025-26/3083 Date:-27.01-2026

e-Notice Inviting Bid No. 02/2025-26
On behalf of the Hon'ble Governor of Rajasthan, Bids of Procurement Conservation and Preservation of The Original archival documents Records (Using Tissue Lamination method) Mending of 1,00,000 sheets Tissue Mending method. (A0/A1/A2/A3/A4/Legal/ Miscellaneous size) of this office is online invited from interested bidders upto 06:00 PM on 17.02.2026. Online Bid Opening date is 17.02.2026 at 3:30 PM. Estimated Cost of Bid is RS. 1.00 Crore (One Crore only). For other particulars of the bid, bidder may be visited on the procurement portal <http://sppp.raj.nic.in> and <http://eproc.rajjasthan.gov.in> of the state. UBN No. of Bid is mentioned below:-
UBN No.: ARC2526SLOB00004
Director Rajasthan State Archives Bikaner

DIPRC/1942/2026

MBM UNIVERSITY, JODHPUR (Central Store)
No.: MBMU/OIC/2025-26/1418 Date :- 02/02/2026

NOTICE INVITING BID
Bids are invited from interested eligible and experienced vendors/suppliers for the supply/provision of the following items/services at MBM University, Jodhpur. All other particulars of the bid may be visited on the portal sppp.rajjasthan.gov.in, eproc.rajjasthan.gov.in and www.mbm.ac.in.
1. Bids vide UBN No: MBM2526WSOB00095 Tender No.69/2025-26 for "Tender for Turnkey Execution of CCTV Cameras, facility in classrooms, laboratory rooms and campus Works for University Campus" in MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹220.00Lakh. rupees and last date of bid submission 21.02.2026, 12:00 Noon.
2. Bids vide UBN No: MBM2526WSOB00094 Tender No.68/2025-26 for "E-Tender for Furniture works of Auditorium and other" in MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹106.00 Lakhs and last date of bid submission 21.02.2026 12:00 Noon.
Raj.Samwad/C/25/19220

OIC-Central Store

OFFICE OF THE DIRECTOR RAJASTHAN STATE ARCHIVES, BIKANER
S.No.: bika/dir/arch/Store/E-NIB-02/2025-26/3083 Date:-27.01-2026

e-Notice Inviting Bid No. 02/2025-26
On behalf of the Hon'ble Governor of Rajasthan, Bids of Procurement Conservation and Preservation of The Original archival documents Records (Using Tissue Lamination method) Mending of 1,00,000 sheets Tissue Mending method. (A0/A1/A2/A3/A4/Legal/ Miscellaneous size) of this office is online invited from interested bidders upto 06:00 PM on 17.02.2026. Online Bid Opening date is 17.02.2026 at 3:30 PM. Estimated Cost of Bid is RS. 1.00 Crore (One Crore only). For other particulars of the bid, bidder may be visited on the procurement portal <http://sppp.raj.nic.in> and <http://eproc.rajjasthan.gov.in> of the state. UBN No. of Bid is mentioned below:-
UBN No.: ARC2526SLOB00004
Director Rajasthan State Archives Bikaner

DIPRC/1942/2026

MBM UNIVERSITY, JODHPUR (Central Store)
No.: MBMU/OIC/2025-26/1418 Date :- 02/02/2026

NOTICE INVITING BID
Bids are invited from interested eligible and experienced vendors/suppliers for the supply/provision of the following items/services at MBM University, Jodhpur. All other particulars of the bid may be visited on the portal sppp.rajjasthan.gov.in, eproc.rajjasthan.gov.in and www.mbm.ac.in.
1. Bids vide UBN No: MBM2526WSOB00095 Tender No.69/2025-26 for "Tender for Turnkey Execution of CCTV Cameras, facility in classrooms, laboratory rooms and campus Works for University Campus" in MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹220.00Lakh. rupees and last date of bid submission 21.02.2026, 12:00 Noon.
2. Bids vide UBN No: MBM2526WSOB00094 Tender No.68/2025-26 for "E-Tender for Furniture works of Auditorium and other" in MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹106.00 Lakhs and last date of bid submission 21.02.2026 12:00 Noon.
Raj.Samwad/C/25/19220

OIC-Central Store

टोंक को पानी व ट्रेन के लिये सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा

टोंक, (निर्स)। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को टोरड़ी सागर बांध एवं चोरेड़ा सागर में डलवाने की मांग के साथ ही नहरों का विस्तार करने एवं टोंक को रेल से जोड़ने आदि की मांग की है।

पत्र में पायलट ने बताया कि बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो के व्यर्थ बहने वाले पानी को नहर का निर्माण करवाकर उसके माध्यम से टोरड़ी सागर बांध एवं चोरेड़ा सागर में डलवाया जाए, जिससे इस नहर के निर्माण से क्षेत्र की उपजाऊ जमीन की सिंचाई के लिए किसानों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। जिले के किसानों की यह लम्बे समय से प्रमुख मांग रही है, पायलट ने टोंक में नहरों का विस्तार करने की मांग भी की है। साथ ही पायलट ने सरकार से

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट

मांग की है कि टोंक को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए पूर्व में स्वीकृत रेल लाइन परियोजना के कार्य में गति लाकर इसे शीघ्र पूर्ण करवाया जाये। शहर के व्यस्तस्थित, आधुनिक एवं सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए टोंक में नगर विकास न्याय की स्थापना की जाए, युवाओं को कृषि की उन्नत

■ बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को टोरड़ी सागर बांध एवं चोरेड़ा सागर में डलवाने सहित कई मांगें रखी

शिक्षा के लिए राजकीय कृषि महाविद्यालय खोला जाए। पायलट ने राज्य सरकार को भेजे गये बजट प्रस्तावों में मिसिंग लिंक एवं गैप बजट प्रस्तावों में मिसिंग लिंक, विभिन्न राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत करवाने सहित नवीन संकाय व अतिरिक्त विषय प्रारम्भ करवाने, राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करवाने व नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खोलवाने तथा टोंक स्थित एनिकटर्स के मरम्मत व सुदृढीकरण कार्यों के प्रस्ताव भिजवाकर आगामी बजट में शामिल किए जाने की मांग की है।

गर्भ में शिशु की मौत, गर्भवती ने भी दम तोड़ा

छबड़ा, (निर्स)। पाली थाना क्षेत्र के जाला गांव निवासी एक गर्भवती के गर्भ में शिशु की मौत हो गई, साथ ही इसका इंफेक्शन शरीर में फैलने से गर्भवती ने भी दम तोड़ दिया। पाली पुलिस ने मृग दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है।

पाली थानाधिकारी अजीतसिंह के अनुसार जाला निवासी कैलाशी बाई (30) पत्नी भगवानसिंह बंजारा को प्रसव पीड़ा होने पर परितन छबड़ा चिकित्सालय लेकर आईं, यहां जांच की तो पता चला कि गर्भ में शिशु की मृत्यु हो गई। साथ ही कुछ देर बाद इंफेक्शन शरीर में फैलने के कारण गर्भवती महिला की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कैलाशी बाई को यह दूसरी दिलीवरी थी।

उल्लेखनीय है दुनिया देखने से पूर्व ही शिशु और मां ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। इस घटना से गांव में मातम पसर गया। हर कोई इस घटना से स्तब्ध था। परिजनों का भी रो-रोकर बुरा हाल है।

सड़क निर्माण में बाधा डालने पर पांच जने गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। पुलिस ने धोलासर गांव में सड़क निर्माण के दौरान राजकार्य में बाधा डालने और पुलिस व प्रशासन के वाहनों पर पथराव करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई जाम्बा पुलिस गांव में दर्ज प्रकरण के आधार पर की गई है।

गिरफ्तार किए गए आरोपी धोलासर निवासी मोहम्मद रफीक, नेक मोहम्मद, इस्माइल ख़ा, अब्दुल रहीम ख़ां और मोहम्मद शरीफ है। इस सभी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रशासन है। ये घटना तीन फरवरी को सरहद धोलासर क्षेत्र में हुई थी। ननेउ से धोलासर जाने वाली सरकारी सड़क के निर्माण और डामरीकरण का कार्य तहसीलदार/कार्यपालक मजिस्ट्रेट लोहावट और पुलिस बल की मौजूदगी में आरएसआरडीसी कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। काम शुरू होने के कुछ देर बाद, गांव के आसपास के कुछ लोगों ने राजकार्य को रोकते हुए बाधा उत्पन्न की। मौके पर मौजूद प्रशासन और पुलिस ने उन्हें सम्मझौता का प्रयास किया और वैधानिक प्रक्रिया की

■ पुलिस व प्रशासन के वाहनों पर पथराव करने का है आरोप

■ जाम्बा पुलिस थाना में दर्ज प्रकरण के आधार पर की गई कार्रवाई

जानकारी दी, लेकिन आरोपियों ने बात नहीं मानी। आरोपियों ने पुलिस और प्रशासन के वाहनों पर पथराव करने का है आरोप। साथ ही पुलिस थाना में दर्ज प्रकरण के आधार पर की गई कार्रवाई

उदयपुर से अजमेर जा रही ट्रेन पर कांच की बोतल फैंकी, युवती घायल

■ कांच की बोतल जनरल डिब्बे में बैठी युवती को लगी, एमबी अस्पताल में भर्ती कराया

थानाधिकारी गोवर्धन सिंह ने बताया कि घायल शिफा (25) को उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिफा अपनी बहन के साथ जनरल डिब्बे में उदयपुर से फतहनगर जा रही थी। राता प्रताप नगर स्टेशन से 11.34 बजे ट्रेन रवाना हुई, करीब 11.47 पर यह घटना हुई। घायल युवती के बताया गए स्थान के अनुसार पुलिस ने घटनास्थल से करीब 4 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र को चिह्नित किया है।

प्रत्यक्षदर्शी एडवोकेट मधु गर्ग ने बताया कि उदयपुर से कपासन में कोर्ट के काम से जा रही थी। मेघवालों की घाटी बरती के पास अचानक एक युवती के चिल्लाने की आवाज आई। हम लोग कुछ दूरी पर थे, भागकर युवती तक पहुंचे। युवती की नाक के पास गंभीर चोट लगी थी, खून बह रहा था। ट्रेन की चैन मैंने खींची। इसके बाद लोगों ने देखा भी मगर दूर तक कोई नजर नहीं आया। करीब एक किलोमीटर आगे देवारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोककर युवती को स्ट्रेचर पर उतराया गया। 15 मिनट बाद एंबुलेंस आई, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई। संभवतया किसी ने बोतल फेंकी होगी, क्योंकि युवती के बैठने की जगह पर वहां कुछ कांच के टुकड़े मिले हैं। रेलवे पुलिस ने भी मौके पर चेकिंग की।

3 6 लाख का डोडा-पोस्त बरामद

रतनगढ़, (निर्स)। मेगा हाइवे पर गुस्वार अलसुबह गश्त के दौरान पुलिस ने एक कार से दो क्विंटल 41 किलो डोडा-पोस्त जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 36 लाख रुपये आंकी गई है।

सीआई गौरव खिड़िया ने बताया कि प्रशिक्षु डीवाईएसपी स्वाति व सब इंस्पेक्टर रतनलाल मय जाब्ता मालासर टोल के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान शहर की ओर से आ रही एक कार चालक ने पुलिस को देखकर वाहन घुमा

लिया। संदेह होने पर पुलिस ने पीछा किया। करीब 25 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद चालक कार को घुमान्दा रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर के पास छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें 14 कट्टों में डोडा-पोस्त मिला। साथ ही कार से पांच अलग-अलग नंबर प्लेटें भी बरामद हुईं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।

पांच वर्षीय बालिका की संदिग्ध मौत : कोटा के रामपुर थाना इलाके में एक 5 वर्षीय मासूम बालिका

की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। प्रथम दृष्टया से बीमारी के चलते बालिका की मौत होना माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार देवनारायण योजना निवासी 5 वर्षीय कृष्णा की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, मामले में मृतका की मां ने बच्ची की मौत को लेकर आशंका जताई है। रामपुर थानाधिकारी भीमसिंह ने बताया कि देवनारायण योजना निवासी कृष्णा (5) की बीमारी के चलते उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई।

मादक पदार्थ सप्लायर गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। फलोदी पुलिस ने मादक पदार्थ एमडीएमए के एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले तीन साल से फरार चल रहा था और उस पर दस हजार रुपए का इनाम घोषित था।

पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने बताया कि कार्रवाई लोहावट थाना प्रभारी हरिसिंह और उनकी टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह चारण और सीओ लोहावट नन्द कुमार के सुपरविजन में की है। प्रकरण के अनुसार दिसंबर 2022 में लोहावट के जम्भेश्वर नगर में आरोपी मनीष शेखाणी के घर से एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 किलो 200 ग्राम अवैध एमडीएमए बरामद किया गया था। उस समय मनीष शेखाणी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। मनीष शेखाणी ने पूछताछ में खुलासा किया था कि उसने ये एमडीएमए अशोक कुमार से खरीदा था। जब्त किए गए अवैध एमडीएमए की बाजार कीमत 3 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी गई थी। थानाधिकारी हरिसिंह और उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बाँछित आरोपी खारा, पुलिस थाना रामसर हाल लक्ष्मीनगर, खादी भंडार के पास बाड़मेर निवासी अशोक कुमार पुत्र चणनाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है और उससे आगे की पूछताछ जारी है।

कार्यालय उप वन संरक्षक (तन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य, धौलपुर

महिला पुलिस थाने के पास हाउसिंग बोर्ड, पुरानी छावनी, धौलपुर पिन कोड 328001 Email ID:-dcfwl.ncs.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एक (ए) /उवसं / वजीधौ., / राघचघर ,2025-26/87

Notice Inviting Tender

Tenders are invited from eligible contractor/firm for Various works for Range Office

क्र. सं.	सूचना संख्या मय दिनांक	कार्य का नाम	Start Date	निविदा (बोली) डाउनलोडिंग एवं अपलोड करने की अंतिम समय एवं दिनांक	UBN NO	अनुमानित लागत रुपये में	निविदा संख्या
1.	RajKaj Ref No.: 20172527 Date 21.01.2026	Improvement Of Basic Facilities Maintenance of Chokli/naka/range office/watch tower etc. of range Chambal Dholpur District- Dholpur	28.01.2026	12:00 PM, 07.02.2026	FOR2526 WSOB051 11	32,00,000	81/2025-26
2.	RajKaj Ref No.: 20172628 Date 21.01.2026	Improvement Of Basic Facilities & Maintenance of Chokli/naka/range office/watch tower etc. of range Vanvihar Dholpur District- Dholpur	28.01.2026	12:00 PM, 07.02.2026	FOR2526 WSOB051 14	43,00,000	82/2025-26
3.	RajKaj Ref No.: 20172981 Date 28.01.2026	राजकीय विद्यालयों में बच्चों के बैठने हेतु Supply and installation of modular plastic Class Room Table (Dual Desk) with Attached Chair ऋय हेतु	28.01.2026	12:00 PM, 07.02.2026	FOR2526 GLOB051 16	24,00,000	69/2025-26
4.	7152332 date 27.01.2026	Solar Photovoltaic Water Pumping Systems (V2) as per MNRSE Specification	27.01.2026	11:00 AM, 06.02.2026	Solarpurc hase	77,00,000	84/2025-26
5.	RajKaj Ref No.: 20102610 Date 28.01.2026	Improvement Of Basic Facility & Maintenance of Choki					

उद्यिमयों के साथ मिलकर पत्थर उद्योग को देश में सिरमौर बनाएंगे : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेईसीसी में इंडिया स्टोन मार्ट का उद्घाटन किया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के पत्थरों की विशिष्टता को विश्व पटल पर अनूठी पहचान है। देशभर के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों, किलों, महलों में राजस्थान का पत्थर उपयोग में लाया गया है। अब राजस्थान का पत्थर उद्योग नई ऊंचाइयों छूने के लिए पूरी तरह तैयार है तथा हम इस उद्योग को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सभी

- मुख्यमंत्री ने स्टोन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्यिमयों को किया सम्मानित

- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किशनगढ़ का मार्बल,राजसमंद, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के पत्थर दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं

उद्यिमयों से प्रदेश में मिलकर पत्थर उद्योग को देश में सिरमौर बनाने की अपील की।शर्मा गुरुवार को जयपुर के जेईसीसी में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीडॉस, रीको और लघु उद्योग भारती को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट प्रदर्शनी नए राजस्थान के संकल्प का प्रतीक है। यह आयोजन भारतीय प्राकृतिक पत्थर उद्योग की शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का



मुख्यमंत्री ने स्टोन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले निदेशक अनिल चौधरी तथा मुकेश चंद्र अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया।

एक वैश्विक मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस स्टोन मार्ट का पहली बार 26 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में वेबसाइट निर्माण, डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन तथा विशाल क्षेत्र में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विपुल खनिज संपदा है। यहां कुल 85 तरह के खनिज उपलब्ध है। मकराना का संगमरमर, किशनगढ़ का मार्बल सहित राजसमंद, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के पत्थर दुनियाभर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के पास न केवल समृद्ध संसाधन हैं, बल्कि सदियों पुरानी शिल्पकला की परंपरा भी है। साथ ही, हमारे कारीगरों की कला निश्चयविख्यात है। हमारे पत्थर को पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री के रूप

में अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है। उन्होंने कहा कि कहा कि उद्योग की असली ताकत हमारे कुशल कारीगर और मेहनतकश श्रमिक हैं। उनके हाथों की कारीगरी ही साधारण पत्थर को अद्भुत कला में बदलती है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर इकॉनोमी बनाया जाए।

इस अवसर पर उद्योग एवं

वाणिज्य मंत्री कपल राज्यवर्धन

राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री

भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में

राज्य सरकार पत्थर उद्योग को आगे

बढ़ाने के लिए तत्पर है। राज्य सरकार

द्वारा निवेश परक नई नीतियों, सिंगल

विंडो क्लियरेंस, प्रक्रियाओं का

सरलीकरण सहित विभिन्न नवाचारों

के माध्यम से उद्यिमयों को राहत दी

जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने

स्टोन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले श्रीराम मेगा स्ट्रक्चर के निदेशक अनिल चौधरी तथा एवर शाइन मार्बल्स के प्रबंध निदेशक मुकेश चंद्र अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इंडिया स्टोनमार्ट 2026 प्रदर्शनी का फीता खेलकर उद्घाटन किया एवं स्टॉल्स का अवलोकन किया।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मुख्य सचिव जी. श्रीनिवास, लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाशचंद्र, आर.के. मार्बल्स के चैयरमेन अशोक पाटनी, ईरान और टर्कई के प्रतिनिधिगण, सहित लघु उद्योग भारती के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, रीको एवं सीडॉस के अधिकारीगण, बड़ी संख्या में उद्यमी, वास्तुकार एवं श्रमिक मौजूद रहे।

अधिकारी दीर्घा खाली मिलने पर स्पीकर वासुदेव देवनानी नाराज़

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को उस समय हंगामे जैसे हालात बन गए, जब शून्यकाल के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी दीर्घा में मौजूद नहीं पाए गए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया। सदन की कार्यवाही सुबह ठीक 11 बजे शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समय पर आसन पर पहुंचे और शून्यकाल की कार्यवाही प्रारंभ करवाई।

इसी दौरान उन्होंने देखा कि अधिकारी दीर्घा पूरी तरह खाली पड़ी हुई है। इस पर अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व में स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि शून्यकाल के दौरान संबंधित

इंडिया पिकफेस्ट में कलाकारों का लाइव प्रदर्शन

जयपुर । पिकफेस्ट का 5 वां संस्करण आज से आरम्भ हुआ। यह एक ऐसा उत्सव है जो हमें एक देश के रूप में परिभाषित करता है: एक ऐसा देश जो कहानियाँ सुनाता है, सपने देखता है, अपने सांस्कृतिक वैभव पर गर्व करने को प्रेरित करता है और अपनी कला, संस्कृति को सहेज कर युवा पीढ़ी को सौंपने की राह बनाता है। यह रंग, संस्कृति और रचनात्मक ऊर्जा का एक आंदोलन है।

इसमें कलावृत्त संस्था द्वारा आयोजित लघु चित्राल की कार्यशाला के साथ साथ अपनी अपनी कलाओं के सिद्धहस्त कलाकार शिल्पगुरु डॉ. इंंदरसिंह सिंह, नीरू छावड़ा, वीरेंद्र बन्नी एवं पृथ्वी राज कुम्हारत अपनी कला का लाइव डेमो द्वारा प्रदर्शित करेंगे तथा युवा पीढ़ी को उसकी तकनीक के बारे में भी बताएंगे और सीखने का भी प्रयास करेंगे।

जयपुर वासियों इस उत्सव का हिस्सा बनें और इसकी रचनात्मकता का अनुभव करें।

- देवनानी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया। सदन की कार्यवाही सुबह ठीक 11 बजे शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समय पर आसन पर पहुंचे और शून्यकाल की कार्यवाही प्रारंभ करवाई

- अध्यक्ष की नाराजगी के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन को आश्वासन दिया कि आगे से ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी

विभागों के अधिकारी सदन में मौजूद रहेंगे, ताकि विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों पर तुरंत संज्ञान लिया जा सके।

उन्होंने कहा कि अधिकारी दीर्घा का खाली रहना गंभीर लापरवाही है और इसे तत्काल सुधारा जाना चाहिए। अध्यक्ष की नाराजगी के बाद संसदीय

कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन को आश्वासन दिया कि आगे से ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि शून्यकाल के दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाएगी। शून्यकाल शुरू होने के समय बड़ी

संख्या में विधायक सदन की लॉबी में मौजूद थे। चूंकि विधानसभा अध्यक्ष आसन पर खड़े थे, इसलिए विधायक सदन में प्रवेश नहीं कर सके। स्थिति को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्पीकर से आग्रह किया कि वे कुछ क्षण के लिए बैठ जाएं, ताकि विधायक सदन में प्रवेश कर सकें।

स्पीकर देवनानी ने सहदयता

दिखाते हुए कुछ देर के लिए आसन पर

बैठकर विधायकों को सदन में आने का

अवसर दिया। विधायकों के सदन में

प्रवेश के बाद कार्यवाही आगे बढ़ाई गई।

इस दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी ने

सभी विधायकों से आग्रह किया कि वे

कार्यवाही शुरू होने से कम से कम पांच

मिनट पहले सदन में पहुंचें, ताकि सदन

के समय का सही उपयोग हो सके।

‘नेता प्रतिपक्ष के बयान में न सकारात्मकता, न विकास की सोच’

- अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सदन में विपक्ष की बोलाती बंद कर दी है
- बालमुकुंद आचार्य ने 5 साल बनाम 2 साल के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए, जनता के साथ मज़ाक नहीं

ने नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य को निरर्थक करार दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के भाषण में न तो कोई सकारात्मक दृष्टिकोण था और न ही विकासोन्मुख सोच दिखाई दी। बेदम ने कहा कि 40 मिनट के भाषण में नेता प्रतिपक्ष ने केवल राहुल गांधी का उल्लेख किया और नेहरू परिवार की चापलूसी करते रहे।

अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सदन में विपक्ष की बोलाती बंद कर दी है। अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल की तुलना पिछली सरकार के 5 वर्षों के कामकाज से करते हुए विपक्ष रिपोट देश की है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आंकड़ों और तथ्यों के साथ बहस की खुली चुनौती दी और कहा कि अगर हिम्मत हो तो बहस करिए, आज सच में मज़ा आ गया जब मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष को जवाब दिया।

विधानसभा परिसर में मीडिया से

रूबरू होते हुए विधायक गुरवीर सिंह

बराड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल

शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने महज

2 वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं, उससे

कांग्रेस पूरी तरह बोखला गई है। उन्होंने

कहा कि इसी का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री

ने सदन में 143 बिंदुओं का विस्तृत

दस्तावेज प्रस्तुत कर कांग्रेस के 5 साल

बनाम भाजपा सरकार के 2 साल के

कार्यों की तुलना रखी।

‘2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय सौर ऊर्जा की क्षमता का लक्ष्य’

जयपुर । राज्सभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा की अनुमानित क्षमता 828 गीगावाट है, जबकि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) के अनुसार राज्य में 150 मीटर ऊँचाई पर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता 284 गीगावाट है। यह आंकड़े साबित करते हैं कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र बनने की क्षमता रखता है। राठौड़ के सवाल के जवाब में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाईक ने सदन को यह जानकारी दी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की सोलर पार्क एवं अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना योजना के अंतर्गत राजस्थान में सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भादला, फलोदी-पोकरण, फतेहगढ़, नोख, पुगल बीकानेर एवं

- केंद्र सरकार की सोलर पार्क एवं अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना योजना के तहत राजस्थान में 10,726 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्वीकृत : मदन राठौड़

जैसलमेर क्षेत्र शामिल है। राज्सभा सांसद राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में अब तक 1,31,057 घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित हो चुके हैं। इससे आम जनता को बिजली बिल से राहत मिल रही है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि रोजगार के विषय में पीएलआई योजना के तहत देशभर में अब तक लगभग 13,600 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं, जिनमें से 3,156 रोजगार जयपुर तथा 20 रोजगार बाड़मेर जिले में सृजित हुए हैं।

मदन राठौड़ द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के विस्तार को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उडके ने बताया कि केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, खेल एवं कौशल

विकास को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। दिसंबर 2025 तक देशभर में कुल 723 ईएमआरएस स्वीकृत किए जा चुके हैं।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देशभर में 42 ईएमआरएस का उद्घाटन किया गया, जिनमें आंध्र प्रदेश में 2 और तेलंगाना में 4 विद्यालय शामिल हैं। इसके साथ ही 50 ईएमआरएस की आधारशिला रखी गई। राजस्थान में इस अवसर पर 3 ईएमआरएस का उद्घाटन किया गया। उन्होंने बताया कि ईएमआरएस में शिक्षा एवं खेल सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक कक्षाएं, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेल उपकरण, स्मार्ट वलस, इंटरनेट सुविधा, संगीत व कला कक्ष, तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है।



शिविर में बी एम वी एस एस संस्था के विशेषज्ञों ने कृत्रिम अंगों को बनाने की पूरी विधि के बारे में जानकारी दी।

जयपुर। सेवा और करुणा की गहरी भावना के साथ, उत्तरी भारत की क्षेत्रीय ग्रैंड लॉज के तत्वावधान में प्रोजेक्ट डिनिटी तथा प्रोमेसस सोसायटी, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण अंगदान (लिव्ब डोनेशन) शिविर का आयोजन किया श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति में किया गया।

शिविर 3 फरवरी को प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन रीजनल ग्रैंड मास्टर राइट वर्षिपफुल ब्रदर पुनीत सोहल तथा जयपुर की तीनों लॉज के वर्तमान वर्षिपफुल मास्टर ब्रदर अमरदीप सिंह, ब्रदर समीर भार्गव और ब्रदर पुष्पेंद्र सिंह राष्ट्रवर ने दीप प्रज्वलन कर किया।

मामले की जांच में इतना समय लगेगा तो कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार : हाईकोर्ट

जयपुर। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में हुए करोड़ों रुपये के घोटालों की जांच नहीं करने से जुड़े मामले में अदालती आदेश की पालना में एसीबी के डीआईजी व मामले में गठित की गई एसआईटी के मुखिया आनंद शर्मा अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें कहा कि एसीबी जांच में इतना समय लगाएगी तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि एक प्रतिशत भ्रष्टाचार पर भी कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है, जो एक चिंतनीय विषय है। अदालत ने एसीबी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की दी गई शिकायतों पर तुरंत प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट दर्ज करें। इसके साथ ही डीआईजी से दो सप्ताह में जांच पूरी कर 23 फरवरी तक प्रागति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश टीएन शर्मा की याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पीसी भंडारी ने कहा कि अदालत ने 6 सितंबर 2024 को टेडरों की जांच के लिए अदालत से समय मांगा। इस पर अदालत ने एसआईटी के मुखिया को दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

- घोटालों की जांच नहीं करने से जुड़े मामले में आदेश की पालना में एसीबी के डीआईजी व मामले में गठित की गई एसआईटी के मुखिया आनंद शर्मा अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें कहा कि एसीबी जांच में इतना समय लगाएगी तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा

कोई जांच नहीं की। जबकि वह लगातार पूरे तथ्यों के साथ एसीबी में मामले पेश करता रहा है। इनमें से केवल एक मामले में एसीबी ने 27 अक्टूबर 2025 को एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में भी चार महीने बाद ही एसीबी ने शिकायतकर्ता के बयान तक दर्ज नहीं किए हैं। वहीं एसीबी ने मामलों की जांच के लिए अदालत से समय मांगा। इस पर अदालत ने एसआईटी के मुखिया को दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

काम कम, ब्रांडिंग ज्यादा; मुख्यमंत्री रील बनाने में व्यस्त : टीकाराम जूली

जयपुर। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की कार्यशैली, प्रशासनिक स्थिति और नीतियों को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में ज़मीनी काम भले ही न हो, लेकिन ब्रांडिंग पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

जूली ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रील बनाने में व्यस्त हैं और केवल ब्रांडिंग के लिए आठ करोड़ रुपये का ठेका दे रहा है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि सरकार ने कई यूथयूथ चैनल बना रखे हैं, जिन पर सौ लोग भी दर्शक नहीं होते।

जूली ने प्रशासनिक हालात पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के जाने के बाद यह चर्चा होने लगी कि अब अगला नंबर किसका है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हमें लगा नहीं कि मुख्यमंत्री ही न बदल जाएं, हालांकि हम चाहते हैं कि यही मुख्यमंत्री पूरे पांच साल पूरे करें।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के भीतर समन्वय का अभाव है। विधायक कह रहे हैं कि मंत्री नहीं

- अभिभाषण पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की कार्यशैली, प्रशासनिक स्थिति और नीतियों को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में ज़मीनी काम भले ही न हो, लेकिन ब्रांडिंग पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं

- नेता प्रतिपक्ष जूली ने विदेश नीति को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहा है

सुनते, मंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनकी कोई नहीं सुन रहा। इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति जताई, जिससे सदन में कुछ देर नोकझोंक भी हुई।

जूली ने कहा कि सरकार के मंत्रियों के कारण कई जगह विधायकों को गांवों में जाने तक में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों पर दादागिरी के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं जनप्रतिनिधियों को धरने की धमकी देनी पड़ रही है,

तो कहीं अधिकारियों द्वारा नए और गरीब जनप्रतिनिधियों का मजाक उड़या जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने विदेश नीति को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहा है। उन्होंने सवाल उठिया कि यह कैसी विदेश नीति है।

जूली ने अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने का भी जिक्र किया और

कहा कि जो टैरिफ पहले शून्य था, वह अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है। जूली ने आरएसएस और वंदे मातरम को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई के समय आरएसएस ने वंदे मातरम और तिरंगे को नहीं अपनाया था। उन्होंने सदन में मौजूद भाजपा विधायकों से सवाल किया कि वंदे मातरम का कौन सा हिस्सा विवादित बताया गया था, लेकिन इस पर कोई विधायक खड़ा नहीं हुआ।

इसके साथ ही जूली ने राइजिंग राजस्थान में हुए 3.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इन समझौतों पर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मालिक नहीं, बल्कि जनता के दूस्ती हैं, इसलिए सवालों के जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है।

जूली ने जेल में सुरंग और जनसुनवाई के दौरान सामने आए जमीन सौदों के मामलों का बवाल देते हुए कहा कि सरकार दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने घर में झांके।

उदयपुर में बदमाशों ने श्रमिक की हत्या की

मजदूरी पर जाते समय लूट की नियत से श्रमिक को रोक बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया था

उदयपुर, (कासं)। हिरणमगरी थाना क्षेत्र जडाव नर्सरी के समीप गुरूवार सवेरे मजदूरी करने जाते समय लूट की नियत से श्रमिक को रोक बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसका पता चलने पर परिजनों ने हंगामा करते हुए लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इस पर सहमति बनने पर मामला शांत हुआ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सविना थाना क्षेत्र विजयसिंह पथिक नगर कच्ची बस्ती निवासी प्रेम गमेली (35) पुत्र मांगीलाल गुरूवार सवेरे हमशरा की तरह मण्डी में मजदूरी करने के लिए जा रहा था। इस दौरान हिरणमगरी थाना क्षेत्र में जडाव नर्सरी

के समीप आए बदमाशों ने लूट की नियत से प्रेम को रोकने पर उसने विरोधक किया तो बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर सविना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच उसे घायलवस्था में सेटेलाईट चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एमबी चिकित्सालय ले गए जहां से उपचार के बाद थाने पहुंचे। वहां ज्यादा समय रुकने पर उसकी तबीयत खराब होने पर चिकित्सालय ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर सविना थाना एसआई लादुराम मय टीम ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की तलाश शुरू की। इधर प्रेम की मृत्यु होने कीपर आए परिजनों ने चिकित्सालय में

- परिजनों ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया**
- चिकित्सकों के खिलाफ रिपोर्ट देने पर मामला शांत हुआ**

हंगामा करते हुए उपचार में लापरवाही बरतने से मौत के लिए जिम्मेदार चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही करने, मुआवजा दिलाने, मृतक के परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने की मांग करते हुए शव लेने से इनकार

कर दिया। गुरूवार सांय तक कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद मृतक की पत्नी नन्दीनी द्वारा चिकित्सकों के खिलाफ रिपोर्ट देने एवं अन्य मांगों पर मदद का आश्वासन देने पर मामला शांत हुआ। मृतक प्रेम का शव एमबी चिकित्सालय मोचरी में रखा है, जिसका शुक्रवार को पोस्टमार्टम होगा। इधर गुरूवार शाम तक सविना थाना एसआई लादुराम द्वारा मामले में किए गए अनुसंधान घटना स्थल हिरणमगरी पुलिस थाना क्षेत्र होने से वहां प्रकरण ट्रांसफर किया गया।

पिता-पुत्र ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की : - उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने पिता-पुत्र व अन्य के खिलाफ बार व रेस्टोरेंट

में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ करने का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित हेमन्त पुत्र लोहरलाल निवासी डागियों का गुड़ा लखावली सुखेर प्रतापगर थाना क्षेत्र में स्थित क्रेजी बार एंड रेस्टोरेंट मैनेजर ने आरोपी हरीश कृपलानी पुत्र आसुमल उसके पुत्र कपील निवासी कन्नामाता अपार्टमेंट तथा अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। उसने बताया कि 5 जनवरी सवेरे मेरे रेस्टोरेंट में आए आरोपी व साथियों ने बार में सोए कर्मचारियों पर हमला कर दिया तथा तोड़फोड़ कर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान



आग लगने से दुकान में रखा सामान जल गया।

झुंझुनूं, (निंस्)। स्थानीय खेमी शक्ति मंदिर के पास समसपुर रोड स्थित शिव मार्केटिंग होलसेल शॉप में बुधवार रात्रि करीब दस बजे अचानक आग लग जाने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। फर्म के मालिक रामकरण पायल ने बताया कि वे चंडीगढ़ गए हुए थे। शाम को उनके भाई विजय ने दुकान बंद की थी। रात्रि को करीब 10 बजे

राहगीरों ने दुकान में से धुआं निकलता देखा और उन्होंने आस-पास के घरों में रहने वालों को बताया तो पता चला। इस पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने पहुंचकर आग बुझाई। आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से होने की आशंका है। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।

अलवर यूआईटी ने अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया



अलवर नगर विकास न्यास की टीम ने कब्जे हटाये।

अलवर, (निंस्)। अलवर नगर विकास न्यास (यूआईटी) की अतिक्रमण निरोधक टीम ने बन्ना राम मीणा की जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।

नगर विकास न्यास की सचिव धाड़गुडे स्नेहल नाना ने बताया कि ग्राम भूगौर झोपड़ी के खसरा नंबर 645 में करीब एक बीघा कृषि भूमि पर बिना न्यास की स्वीकृति और भू-परिवर्तन कराए ठोवल सड़क बनाकर अवैध प्लॉटिंग और चारदीवारी की जा रही

थी। जमीन पर बन्नाराम मीणा सहित मुकेश, बृजमोहन, महेंद्र, संतोष देवी, छात्राराम व अन्य द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसे टीम ने तोड़ दिया। इसके अलावा अंबेडकर नगर की वेयरहाउस योजना में सड़क के मुख्य हिस्से पर लगाए गए अवैध खोखे और ठेलों को हटाय़ा गया। वहीं बिना अनुमति की जा रही अवैध ट्रक पार्किंग को भी हटाकर न्यास की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

अवैध हथियार के साथ दो हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

सूरजगढ़ में कोर्ट के बाहर गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में कार्रवाई की

पिलानी, (निंस्)। स्थानीय पुलिस ने चिड़ावा डीएसटी टीम की मदद से सूरजगढ़ थाने के दो हिस्ट्रीशीटरों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों हिस्ट्रीशीटरों ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर दो दिन पहले ही सूरजगढ़ कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी पूर्व पंचायत समिति सदस्य नीरज भंडिया की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की

- पीलानी पुलिस ने चिड़ावा डीएसटी टीम की मदद से कारवाई कर आरोपियों को पकड़ा**



पिलानी पुलिस ने चिड़ावा डीएसटी टीम की मदद से एक पिस्टल, चार कारतूस और कैपर गाड़ी जब्त की।

की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की ओर भाग गए, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर गाड़ी रूकवाई, जिसमें सवार सूरजगढ़ थाना इलाके के दोबड़ा निवासी 22 वर्षीय आकाश उर्फ शूटर पुत्र रामसिंह नाई तथा स्वामी सेही निवासी ललित धानक उर्फ लीता पुत्र जसवंत धानक की तलाशी ली गई तो एक अवैध पिस्टल और चार कारतूस मिले। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक पिस्टल, चार कारतूस और कैपर गाड़ी को जब्त कर लिया है। पूछताछ के दौरान दोनों गिरफ्तार युवकों ने दो दिन पहले सूरजगढ़ कोर्ट के बाहर

गाड़ी से तोड़फोड़ करने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार दोनों युवक सूरजगढ़ थाने के हिस्ट्रीशीटर है। ललित धानक को के खिलाफ विभिन्न थानों में 10 तथा आकाश उर्फ शूटर के खिलाफ विभिन्न थानों में 15 मामले दर्ज है। सीआई चंद्रभान ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जिन्हें रिमांड पर लाकर पूछताछ की जाएगी। आरोपियों से और भी मामलों का खुलासा हो सकता है। पिलानी पुलिस द्वारा पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपियों को सूरजगढ़ पुलिस तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार करेगी।

ऑक्सीजन सिलेण्डर से भरी लोडिंग टेक्सी की कार से फिर्दत : जोधपुर के बोरानाडा कंटेनर डिपो के सामने एक गंभीर सड़क दुर्घटना हो गई। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रही लोडिंग टेक्सी और गलत दिशा से आ रही ट्रक़ा कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं टेक्सी चालक घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब टेक्सी बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जा रही थी। ट्रकवर इतनी तेज थी कि किया कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार चालक को कोई गंभीर चोट

नहीं आई और वह सुरक्षित रहा। वहीं लोडिंग टेक्सी चालक हैंडल और टेक्सी के बीच बुरी तरह फंस गया। ट्रककर के बाढ़ टेक्सी का अगला हिस्सा धुक गया, जिससे चालक को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए करीब 15 से 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद टेक्सी का हैंडल तोड़कर चालक को बाहर निकाला। हादसे में टेक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर बोरानाडा पुलिस मौके पर पहुंची।

बैंक में दो-दो सौ के 177 नकली नोट जमा कराए, मामला दर्ज

जानकारी में सामने आया है कि आरोपी सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है

- पुलिस को आशंका है कि यह मामला किसी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है**

बीकानेर, (निंस्)। शहर में नकली नोटों के चलन का मामला सामने आया है। यहां मुरलीधर व्यास नगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में नकली नोट पहुंचने के बाद नयाशहर थाने में मामला दर्ज कराया है। यहां दो-दो सौ रुपए के 177 नोट जब्त किए हैं।

मुरलीधर व्यास कॉलोनी स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में एक

खताधारक ने नगद रुपए जमा कराए

हैं। बैंक प्रशासन ने तुरंत पुलिस को

सूचना दी। इस मामले में बैंक शाखा

प्रबंधक पुरुषार्थ पुरोहित की रिपोर्ट पर

नया शहर थाना पुलिस ने श्याम सुंदर

नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

- पुलिस को आशंका है कि यह मामला किसी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है**

किया है। यह घटना 2 फरवरी की बताई जा रही है, जब आरोपी ने अपने खाते में 200-200 रुपये के नोट जमा करवाए थे। बैंक में नियमित जांच के दौरान नोट संदिग्ध पाए गए, जिसके बाद मशीनों से जांच कराई गई। जांच में कुल 177 नोट नकली निकले। इसके बाद बैंक अधिकारियों ने नकदी जब्त कर पुलिस को सूचना दी और आवश्यक

दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे।

नया शहर थानाधिकारी कविता पुनिया ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि आरोपी सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास नकली नोट कहां से आए और क्या इसके पीछे किसी बड़े गिरोह की भूमिका है। पुलिस को आशंका है कि यह मामला किसी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है, इसलिए जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है।

अजमेर के जेएलएन अस्पताल में दुनिया का 43वां दुर्लभ ऑपरेशन सफल

- डॉक्टरों ने 59 वर्षीय महिला की अत्यंत दुर्लभ बीमारी ‘एस्ट्रो डुओडेनल इंटुससेप्शन’ की सफल सर्जरी कर नया जीवन दिया**

- यह मामला न केवल प्रदेश का पहला, बल्कि दुनिया का 43वां और भारत के गिने-चुने दुर्लभतम मामलों में से एक माना जा रहा है**

जब एंडोस्कोपी और सीटी स्कैन किया गया, तो आंतों में समस्या के संकेत मिले। सर्जिक निदान के लिए डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन टेबल पर जब डॉक्टरों ने जांच की, तो वे भी हैरान रह गए। यह सामान्य समस्या नहीं बल्कि एस्ट्रो डुओडेनल इंटुससेप्शन थी, जिसमें पेट का एक हिस्सा खुद ही आंत के अंदर धंस जाता है।

निजी अस्पतालों में लाखों के खर्च वाली यह जटिल सर्जरी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पूर्णतः नि:शुल्क की गई। डॉ. अनिल शर्मा के साथ डॉ. एमपी शर्मा एंडोस्कोपिस्ट और एनेस्थीसिया टीम का विशेष योगदान रहा। इस केस की दुर्लभता को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय

मेडिकल जर्नल्स में प्रकाशन के लिए भेजा जा रहा है।

डॉ. अनिल के शर्मा, वरिष्ठ सर्जन का कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि विश्वस्तरीय चिकित्सा गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। यह सर्जरी हमारी टीम की क्षमता और सेवा भाव का जीवंत प्रमाण है।

डॉ. अरविंद खरे, अध्यक्ष जेएलएन मेडिकल अस्पताल ने जेएलएन मेडिकल कॉलेज टीम को बधाई दी और बताया कि अब राजस्थान के मरीजों को जटिल से जटिल सर्जरी के लिए बड़े महानगरों या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। अजमेर का जेएलएन मेडिकल कॉलेज अब विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस है।

अनुसूचित जाति आयोग ने आयुक्त कॉलेज शिक्षा को फिर नोटिस भेजा

- पूर्व के तीन नोटिस का जवाब नहीं देने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नाराज**

प्रोफेसर होने के कारण जैसा कि अन्य

महाविद्यालयों में होता है। महाविद्यालय

के कार्यवाहक प्राचार्य का चार्ज प्राथी को

19.11.2025 से दिया हुआ था।

लेकिन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा

राजस्थान के संयुक्त निदेशक एचआरडी

डॉ.शोभाराम शर्मा ने 20.11.2025

को अनुसूचित जाति के प्रोफेसर की

वरिष्ठता को जानबूझकर नजरअंदाज

कर अत्यंत जूनियर डॉ.बनवारी लाल

मेनावत को महाविद्यालय चार्ज के

आदेश दे दिए। डॉ.मेनावत चयनित

प्राचार्य नहीं है जैसा कि भ्रम फैलाया जा

रहा है। इनसे मिलीभगत रखने

वाले,पक्षपात करने वाले अधिकारियों ने

जोधपुर, (कासं)। बालेसर में चामू

पंचायत समिति की प्रहलादपुरा ग्राम

पंचायत के पटवारी दिनेश जाणी को

निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों से

कथित अवैध वसूली का वीडियो सामने

आने के सात दिन बाद उपखंड

अधिकारी ने यह कारवाई की। निलंबन

अवधि में पटवारी का मुख्यालय

बालेसर उपखंड कार्यालय रहेगा।

जानकारी के अनुसार यह वीडियो

गत तीस जनवरी को वायरल हुआ था।

इसमें पटवारी बनियान पहने एक कमरे

में बैठे दिख रहे हैं, जबकि उनके पास

बैठे कुछ लोग हाथ में कागज लिए रुपए

इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं।

हालांकि, यह वीडियो एक-दो साल

पुराना बताया जा रहा है। वीडियो

तथ्य छुपाए हैं। अनुसूचित जाति के

प्रो.रमेश बैरवा ने यह भी बताया

कि आयोग के नोटिस की परवाह किए

बिना कुछ दिन पूर्व आयुक्तालय कॉलेज

शिक्षा के 29 जनवरी के आदेश से प्राथी

को एक बार फिर वंचित कर उन्हीं

जूनियर डॉ.बनवारी लाल मेनावत को

राजकीय महाविद्यालय के आहरण एवं

निलतण अधिकारी (डीडीओ) की पावर

दे दी गई है। इससे इन्हें फिर मानसिक

पीड़ा हुई है।

प्रो.रमेश बैरवा ने यह भी बताया

कि आयोग के नोटिस की परवाह किए

बिना कुछ दिन पूर्व आयुक्तालय कॉलेज

शिक्षा के 29 जनवरी के आदेश से प्राथी

को एक बार फिर वंचित कर उन्हीं

जूनियर डॉ.बनवारी लाल मेनावत को

राजकीय महाविद्यालय के आहरण एवं

निलतण अधिकारी (डीडीओ) की पावर

दे दी गई है। इससे इन्हें फिर मानसिक

पीड़ा हुई है।

प्रो.रमेश बैरवा ने यह भी बताया

कि आयोग के नोटिस की परवाह किए

बिना कुछ दिन पूर्व आयुक्तालय कॉलेज

शिक्षा के 29 जनवरी के आदेश से प्राथी

को एक बार फिर वंचित कर उन्हीं

जूनियर डॉ.बनवारी लाल मेनावत को

राजकीय महाविद्यालय के आहरण एवं

निलतण अधिकारी (डीडीओ) की पावर

दे दी गई है। इससे इन्हें फिर मानसिक

पीड़ा हुई है।

प्रो.रमेश बैरवा ने यह भी बताया

कि आयोग के नोटिस की परवाह किए

बिना कुछ दिन पूर्व आयुक्तालय कॉलेज

शिक्षा के 29 जनवरी के आदेश से प्राथी

को एक बार फिर वंचित कर उन्हीं

जूनियर डॉ.बनवारी लाल मेनावत को

राजकीय महाविद्यालय के आहरण एवं

निलतण अधिकारी (डीडीओ) की पावर

दे दी गई है। इससे इन्हें फिर मानसिक

पीड़ा हुई है।

प्रो.रमेश बैरवा ने यह भी बताया

कि आयोग के नोटिस की परवाह किए

बिना कुछ दिन पूर्व आयुक्तालय कॉलेज

शिक्षा के 29 जनवरी के आदेश से प्राथी

को एक बार फिर वंचित कर उन्हीं

जूनियर डॉ.बनवारी लाल मेनावत को

राजकीय महाविद्यालय के आहरण एवं

निलतण अधिकारी (डीडीओ) की पावर

दे दी गई है। इससे इन्हें फिर मानसिक

पीड़ा हुई है।

प्रो.रमेश बैरवा ने यह भी बताया

कि आयोग के नोटिस की परवाह किए

बिना कुछ दिन पूर्व आयुक्तालय कॉलेज

शिक्षा के 29 जनवरी के आदेश से प्राथी

को एक बार फिर वंचित कर उन्हीं

जूनियर डॉ.बनवारी लाल मेनावत को

राजकीय महाविद्यालय के आहरण एवं

निलतण अधिकारी (डीडीओ) की पावर

दे दी गई है। इससे इन्हें फिर मानसिक

पीड़ा हुई है।

प्रो.रमेश बैरवा ने यह भी बताया

कि आयोग के नोटिस की परवाह किए

बिना कुछ दिन पूर्व आयुक्तालय कॉलेज

शिक्षा के 29 जनवरी के आदेश से प्राथी

को एक बार फिर वंचित कर उन्हीं

जूनियर डॉ.बनवारी लाल मेनावत को

राजकीय महाविद्यालय के आहरण एवं

निलतण अधिकारी (डीडीओ) की पावर

दे दी गई है। इससे इन्हें फिर मानसिक

पीड़ा हुई है।

प्रो.रमेश बैरवा ने यह भी बताया

कि आयोग के नोटिस की परवाह किए

बिना कुछ दिन पूर्व आयुक्तालय कॉलेज

शिक्षा के 29 जनवरी के आदेश से प्राथी

को एक बार फिर वंचित कर उन्हीं

जूनियर डॉ.बनवारी लाल मेनावत को

राजकीय महाविद्यालय के आहरण एवं

निलतण अधिकारी (डीडीओ) की पावर

दे दी गई है। इससे इन्हें फिर मानसिक

पीड़ा हुई है।

प्रो.रमेश बैरवा ने यह भी बताया

कि आयोग के नोटिस की परवाह किए

बिना कुछ दिन पूर्व आयुक्तालय कॉलेज

शिक्षा के 29 जनवरी के आदेश से प्राथी

को एक बार फिर वंचित कर उन्हीं

जूनियर डॉ.बनवारी लाल मेनावत को

राजकीय महाविद्यालय के आहरण एवं

निलतण अधिकारी (डीडीओ) की पावर

मुख्यमंत्री ने दो वर्ष की उपलब्धियों के दस्तावेज सदन पटल पर रखे

राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए भजनलाल ने कहा, दो वर्ष में राजस्व घाटा 8000 करोड़ कम किया

जयपुर, 5 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुईं बहस का जवाब देते हुए पहली बार दो वर्ष की उपलब्धियों का दस्तावेज सदन के पटल पर रखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में सड़क, बिजली, पानी, कृषि, महिला, युवा कल्याण सहित विभिन्न

- **“खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष, इसे बचाने के लिये कानून लायेंगे।”**
- **“देश की 11 जनकल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान पहले स्थान पर है।”**
- **“वर्ष 2023 की तुलना में 2025 में 14.13 प्रतिशत अपराध में कमी आई।”**

क्षेत्रों में वर्तमान सरकार द्वारा दो साल में किए गए कार्यों का तुलनात्मक ब्यूरा सदन के सामने रखा और कहा कि राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को न केवल स्थिरता दी, बल्कि उसे गति और दिशा भी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष भी है, राजस्थान की पहचान भी है, जिसकी बढ ते हुए रेगिस्तान को रोकने में हमेशा सार्थक



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुईं बहस का जवाब दिया।

भूमिका रही है। शर्मा ने कहा कि हम राज्य के कल्पवृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी लाएंगे, जिससे प्रदेश में खेजड़ी संरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया और केवल दो वर्षों में 2० करोड़ पौधे लगाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों के कार्यकाल में हमारा प्रदेश 11 जनकल्याणकारी योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इसी प्रकार 5 राष्ट्रीय योजनाओं में दूसरे स्थान पर और 9 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तीसरे स्थान के

साथ ही दो प्रमुख आयामों में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का सम्मान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम पांच साल के भीतर किसान सम्मान निधि को दोगुना करेंगे। दो साल के भीतर ही हम इसे डेढ़ गुना कर चुके हैं।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों से वित्त 2 वर्षों से अपराध के ग्राफ में निरन्तर कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में

14.13 प्रतिशत अपराधों में कमी दर्ज की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार के मामलों में 28 प्रतिशत तथा महिला अपराधों में 1० प्रतिशत की कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान तो समय पर कर ही रही है, साथ ही, पूर्ववर्ती सरकार की बकाया पेंशन का भी भुगतान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के वादे के अनुरूप हमारी सरकार प्रत्येक वर्ष किए गए नीतिगत निर्णय और विकास के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर जाएगी।

ईसाई रीति से हुए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिगु अदालत ने कहा कि विवाह केवल निजी संबंध नहीं, बल्कि एक वैधानिक स्थिति है। जिससे उत्तराधिकार, सामाजिक सुरक्षा और भरण पोषण सहित अन्य परिणाम उत्पन्न होते हैं। जनहित याचिका में अधिवक्ता सुसेन मैथ्यू ने अदालत को बताया कि प्रदेश में ईसाई युगल ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत विवाह करते हैं। इस अधिनियम के तहत विवाह कराने वाले पादरी की ओर से जो विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसे ही पंजीकृत किया जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद इन विवाहों को नगर

निगम के रजिस्ट्रार अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2०09 की गलत तरीके से व्याख्या कर पंजीकृत करने में आनाकानी करते हैं। याचिका में कहा गया कि विवाह पंजीकरण नहीं होने से ईसाई दंपतियों को पासपोर्ट और वीजा सहित अन्य सरकारी सेवाओं के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह पादरी की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्रों का पंजीकरण करें।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम के प्रावधान ईसाई विवाहों पर लागू नहीं होता है।

संसद में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
प्रधानमंत्री के जवाब के 3समय की प्रतिक्रिया के बारे में विशेष चर्चा हुई।

बैठक में खड़गे के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में द्रमुक के तिरुचि एन. शिवा, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा, शिव सेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ,इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी बशीर अहमद सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया।

बाद में कांग्रेस संसदीय दल के नेताओं की भी पार्टी के सांसद दल के कार्यालय में बैठक हुई जिसमें गांधी सहित पार्टी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया।

प.बंगाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कांग्रेस को एकतरफा समर्थन देना चाहिए। प्रदेश के एक कांग्रेस नेता ने कहा, “यह ठीक है कि आप अपने घर में मजबूत हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों को कुचल डालों।”

“अकेले चलने के फैसले पर हरी झंडी मिलने की पुष्टि करते हुए, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के एकमात्र सांसद इशा खान चौधरी ने कहा कि इस फैसले को राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। कांग्रेस बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भी इस फैसले की पुष्टि की।

‘दुनिया का सबसे अमीर देश भी घुसपैठियों को निकाल रहा है’

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम और सरकार के आर्थिक सुधारों सहित विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के विरोध पर गुरुवार को राज्य सभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सोच और राजनीति पर तीखे हमले किये।

मोदी ने विपक्ष के बहिष्कार के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा का जवाब देते हुए एसआईआर के विरोध के लिए तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए तृणमूल के लोगों को अपने गिरिबां में झांकने की सलाह दी और कहा कि तृणमूल पतन के नये मानदंड बना रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार को निर्मम सरकार बताते हुए कहा कि वह लोगों को भविष्य अंधकार में डाल रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे समृद्ध देश भी अपने यहां से गैर कानूनी नागरिकों को निकाल रहा है, लेकिन तृणमूल के लोग घुसपैठियों की

अल-फलाह चेयरमैन सिद्दीकी चार दिन पुलिस हिरासत में

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। एक निचली अदालत ने विवादों में घिरे अल-फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को कथित धोखाधड़ी और वित्तीय कदाचार के मामले में चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

सिद्दीकी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की पुछताछ के लिए चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायतों के बाद शुरू की गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) ने उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अपराध शाखा ने यूजीसी की शिकायतों के आधार पर सिद्दीकी के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की थीं।

मेघालय में अवैध कोयला खदान में धमाका, 1 8 मजदूरों की मौत

खदान में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है

- **प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा दु:ख जताया, मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रु. व घायलों को 50,०00 रु. देने की घोषणा की।**

ने मोदी के हवाले से एक पोस्टर में कहा, “मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स में हुई दुर्घटना से व्यथित हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।” मोदी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख

रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,०00 रुपये दिए जाएंगे।

आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसारमेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को “अवैध कोयला खदान में विस्फोट होने से कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य के फंसे होने की आशंका है। पुलिस महानिदेशक आई नोंगरंग ने यह जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि यह घटना थांगस्कु इलाके में हुई और बचाव दल तलाशी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमने अब तक 16 शव बरामद किए हैं, लेकिन विस्फोट के समय खदान के अंदर मौजूद लोगों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।

‘सदन में प्रमंत्री के साथ हादसा हो सकता था, मैंने उन्हें सदन में आने के लिए मना किया था’

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया बेहद गंभीर चौंकाने वाला खुलासा

- **ओम बिड़ला ने कहा उन्हें खुफिया जानकारी के साथ सदन के भीतर के हालात से इनपुट मिला था कांग्रेस के सांसद प्रमंत्री के कुर्सी के पास आकर हंगामा कर तथा अनहोनी करने की योजना बना रहे हैं।**

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने गुरुार को एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने ही कल (बुधवार) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने से रोका था। बिड़ला ने आशंका जताई

कि अगर पीएम मोदी कल सदन में आते, तो उनके साथ कोई अप्रत्याशित और अग्रिय घटना घट सकती थी। स्पीकर ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी और सदन के भीतर के हालात से यह इनपुट मिला था कि

आसाराम के अहमदाबाद आश्रम पर बुलडोजर चलेगा

अहमदाबाद, ०5 फरवरी। आसाराम का अहमदाबाद स्थित आश्रम टूटेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को मोटेरा आश्रम ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में शहर के मोटेरा इलाके में स्थित भूखंड को खाली कराने की सरकारी कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार के लिए आश्रम की जमीन अपने कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया है। आश्रम की 45,०00 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन पर 203० कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। वर्तमान में इस जमीन की मार्केट वैल्यू 5०0 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।

गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस वैभवी नानावटी ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि आश्रम में नियमों का उल्लंघन हुआ। उस जमीन का विकास परियोजना को जबरन भी है, इसलिए सरकार की मांग सही है।

इस फैसले के बाद अहमदाबाद नगर निगम कभी भी आश्रम में बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर पब्लिक प्रॉसीक्यूटर जीएच विर्क ने कोर्ट को बताया कि यह जमीन

- **गुजरात हाईकोर्ट ने आश्रम की जमीन लेने की सरकारी कार्यवाही को सही ठहराया**

दशकों पहले सीमित धार्मिक उपयोग के लिए दी गई थी। लेकिन, धीरे-धीरे इसका विस्तार होता चला गया।

जबकि, भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार इसका व्यवसायिक उपयोग, अनधिकृत निर्माण और बिना अनुमति विस्तार प्रतिबंधित था। आश्रम परिसर में करीब 32 अवैध स्ट्रक्चर बना लिए गए, जो कानूनी सीमाओं से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एएमसी) ने आश्रम को कई बार नोटिस भेजे थे। इसके बाद 21 जनवरी 2०26 को नगर निगम ने आश्रम का आवेदन भी खारिज कर दिया था।

साबरमती नदी किनारे इस आश्रम की स्थापना आसाराम ने 1972 में की थी। आसाराम ने यहां सबसे पहले एक कुटिया बनाई थी, जिसे मोक्ष कुटिया के रूप में पहचाना जाता था। धीरे-धीरे इसी कुटिया के आसपास निर्माण कार्य होता चला गया और बाद में इसे आसाराम मोटेरा आश्रम के नाम से पहचाना जाने लगा।